



2026:AHC:56442

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 7089 वर्ष 2026

कांता सैनी और 2 अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : हेमेंद्र कुमार, राजेश मिश्रा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय सं. - 70

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दायर पूरक हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री पी.के.राय, राज्य-प्रतिवादियों के लिए एजीए को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
3. यह जमानत आवेदन संख्या 0008 वर्ष 2026 के मामले में आरोपी-आवेदकों **कांता सैनी, बहादुर और संदीप उर्फ चोमू** की ओर से धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3), 191(2) और 191(3) बीएनएस, पीएस नेहतौर, जिला बिजनौर के तहत जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. संक्षेप में, एफआईआर, कांता सैनी, बहादुर, में निहित आरोपों के अनुसार, नामित आरोपी आवेदकों और 5-6 अज्ञात व्यक्तियों ने घायल वीरेश पाल, विनोद कुमार और अनिल कुमार को कठोर और कुंद वस्तु और तेज धार वाले हथियार से आग्नेयास्त्र से घायल कर दिया है।

5. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आरोपी-आवेदकों ने एफआईआर में आरोप के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है और इस मामले में उन्हें झूठा फंसाया गया है। आवेदक संख्या 1 और 2 कांता सैनी और बहादुर का नाम है, जबकि आवेदक संख्या 3 संदीप उर्फ चोमू का नाम एफआईआर में नहीं है। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में जांच के दौरान उनका नाम बहुत देर से सामने आया। घायल व्यक्तियों को विशिष्ट चोट पहुंचाने के संबंध में एफआईआर में या घायल व्यक्तियों के बयानों में आवेदकों को कोई विशिष्ट और विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। घायल वीरेश पाल, विनोद कुमार और अनिल कुमार ने सभी आरोपियों को कठोर और कुंद वस्तु और धारदार हथियार से चोट पहुंचाने के संबंध में सामान्य भूमिका सौंपी। माना जाता है कि घायल वीरेश पाल की मेडिकल रिपोर्ट में तीन कटे हुए घाव दर्ज किए गए हैं और अन्य चोटों के घाव घायल हैं, लेकिन रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट नहीं है कि किसने कटे हुए घाव किए हैं। अन्य घायल विनोद कुमार और अनिल कुमार की चोटें साधारण प्रकृति की हैं। आगे यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक संख्या 1 कांता सैनी का सात मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिन्हें दूसरे पूरक हलफनामे के पैरा -3, 4, 5 और 6 में और पहले पूरक हलफनामे के पैरा, 2, 3 और 4 में समझाया गया है। आवेदक संख्या 2 का दो मामलों का आपराधिक इतिहास है जिसे पहले पूरक हलफनामे के पैरा 5 और 6 में समझाया गया है। आवेदक 07.01.2026 से जेल में हैं। निवेदन यह है कि मुकदमे के निष्कर्ष में पर्याप्त समय लगेगा और जमानत पर रिहाई के मामले में उसके न्याय के रास्ते से भागने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए जमानत की मांग की गई है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदकों की जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदकों की बेगुनाही को पूर्व परीक्षण चरण में नहीं ठहराया जा सकता है, इसलिए, वे किसी भी भोग के लायक नहीं हैं। यदि आवेदकों को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे फिर से इसी तरह की गतिविधियों में शामिल होंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे।

7. ऊपर उल्लिखित पक्षों की प्रस्तुतियों के साथ-साथ इस तथ्य पर भी विचार करने के बाद कि हालांकि आवेदक संख्या 1 और 2 कांता सैनी और बहादुर का नाम एफआईआर में है, लेकिन आवेदक संख्या 3 संदीप उर्फ चोमू का नाम नहीं है, आवेदकों को एफआईआर में या तीन घायल व्यक्तियों के बयानों में कठोर और कुंद वस्तु और तेज धार वाले हथियार से चोट पहुंचाने के संबंध में कोई विशिष्ट और अलग भूमिका नहीं सौंपी गई है, सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य आरोप लगाए गए हैं, घायल व्यक्तियों की अधिकांश चोटें प्रकृति में साधारण हैं, जिनकी चोटें तेज धार वाली हैं, यह स्पष्ट नहीं है और मुकदमे के समापन के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2024 (एससी) मुकदमा 677** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पैराग्राफ संख्या 53 पर विचार करते हुए, **भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713 और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2022) 10 एससीसी 51** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदकों को उनके व्यक्तिगत बांड और दो भारी जमानतदारियों पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में है: -

(i) आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे या गवाहों को धमकी नहीं देंगे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



- (ii) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेंगे कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वे साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेंगे।
- (iii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या संबंधित न्यायालय द्वारा निर्देशित प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।
- (iv) आवेदक (i) मामले की सुनवाई, (ii) आरोप तय करने और (iii) अभियुक्तों के खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली परिस्थितियों को समझाने के लिए व्यक्तिगत रूप से बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।
- (v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, विचारण न्यायालय उनके विरुद्ध कड़ाई से कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा।
8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।
9. बांड स्वीकार करने से पहले आवेदकों और जमानतदारों की पहचान और निवास प्रमाण को संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

मार्च 19, 2026

आशा

(न्यायमूर्ति संतोष राय)

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"